

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-2358/2016/बूंदी

श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री रमेश कुमार गौड़, जाति ब्राह्मण, निवासी पुरानी कोतवाली, तम्बोलियों की गली, बूंदी जिला बूंदी।
...प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप-पंजीयक बूंदी।
2. पंकज पुत्र श्री जगदीश नागपाल, जाति पंजाबी, निवासी 2-बी-1 विकास नगर, बूंदी।
...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस. के. पुरोहित

अभिभाषक

...प्रार्थीया की ओर से

श्री आर. के. अजमेरा

उप-राजकीय अभिभाषक

....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

नाम तर्क किया गया

...अप्रार्थी सं. 2

निर्णय दिनांक : 31.05.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) कोटा (जिसे आगे 'कलक्टर' कहा गया है) के आदेश दिनांक 10.08.2016 प्रकरण संख्या 148/2015 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप-पंजीयक बूंदी, द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया के पक्ष में अप्रार्थी संख्या-2 ने एक विक्रय पत्र तहरीर कर दिनांक 11.01.2010 को उप-पंजीयक, बूंदी के यहां वास्ते पंजीयन प्रस्तुत किया। उप-पंजीयक द्वारा उक्त दस्तावेज 92,000/- रुपये की मालियत पर दस्तावेज संख्या 93 दिनांक 11.01.2010 पंजीयन कर प्रार्थीया को लौटा दिया। महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ने अपने निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 2006-07 से 2010-11 में आक्षेप किया कि राजस्थान मुद्रांक अनुसूची के आर्टिकल 21(1) के अनुसार अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य होगा। राजस्थान मुद्रां नियमावली 2004 के निर्णय 58 के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित दरों या महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) द्वारा निर्धारित दरों में जो भी उच्चतर हो के आधार पर किया जावेगा। पंजीयन शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 1 प्रतिशत

२११

लगातार.....2

अधिकतम 25,000/- रुपये एवं दिनांक 9 अप्रैल 2010 से अधिकतम 50,000/- रुपये प्रभार्य होगा। महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) द्वारा जारी परिपत्र 02/2004 के बिन्दु 5(ब) के अनुसार यदि सम्पत्ति कोने पर स्थित है तो उक्त सम्पत्ति को कीमत की गणना में भूमि की कीमत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार्य होगा।

उ.प.का. के 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा में आक्षेप लिया (अक्टूबर 2010 से नवम्बर 2011) कि 123 विक्रय लेख पत्रों में वाणिज्यिक दरों के स्थान पर आवासीय दर लगाने, कोने पर स्थित भूखण्ड पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त भूमि की कीमत प्रभार्य न करने, सिंचित भूमि की दरें लागू न करने व निर्माण पर पूर्ण विवरण के अभाव में गलत छूट दिये जाने के कारण कम मूल्यांकन किया गया। उपरोक्त निरीक्षण की पालना में उप-पंजीयक, बूंदी द्वारा प्रार्थीया से बकाया राशि प्राप्त करने हेतु एक रेफरेन्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। महालेखाकार, राजस्थान जयपुर के आक्षेप को सही मानकर उप-पंजीयक, बूंदी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने एकपक्षीय निर्णय दिनांक 10.08.2016 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थीया के दस्तावेज की मालियत 5,28,800/- रुपये निर्धारित कर कमी स्टाम्प 17,480/- रुपये, कमी पंजीयन शुल्क 43,370/- रुपये, जी.पी.ए. 2 प्रतिशत 8,740/- रुपये, तावान 20,980/- रुपये, कुल 51,570/- रुपये प्रार्थीया से वसूल कर राजकोष में जमा कराने के आदेश पारित किये जिससे व्यथित होकर प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 का नाम विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया के निवेदन पर इस आधार पर तर्क किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 विक्रेता है तथा मुद्रांक कर आदि की देयता का दायित्व प्रार्थीया क्रेता का है।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया ने कथन किया कि दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति आवासीय है तथा मौके पर खाली भूखण्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65 के अन्तर्गत जांच की है व न ही निर्णय में रेफरेन्स के तथ्यों को स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण स्पष्ट किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय Non Speaking एवं Non Reasoned है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-
8. विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित रेफरेन्स का कोई स्पष्ट आधार उपलब्ध नहीं है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अध्याय-II के पृष्ठ संख्या 13 व 14 की फोटोप्रति संलग्न है जिसमें 123 विक्रय लेखों के संबंध में उल्लेख किया गया है परन्तु प्रश्नगत विक्रय पत्र के संबंध में क्या विशिष्ट आक्षेप लिया है, स्पष्ट नहीं है। उप-पंजीयक ने भी रेफरेन्स दिनांक 11.06.2015 में रेफरेन्स के आधार का उल्लेख नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में रेफरेन्स के आधार का कोई उल्लेख नहीं किया है।
9. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है।

कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स के तथ्यों की विवेचना किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कोई आधार स्पष्ट नहीं किया है व न ही रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अपीलारी अधिकारी के आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of

257

2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :-

"... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regular hearing."

"A litigant has legitimate expectation of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretion by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally ceases. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent. Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of correction is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appear to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system."

उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

10. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना-विश्लेषण सहित निर्णय पारित नहीं करने के कारण विधिसम्मत नहीं होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अप्रार्थी संख्या 2 को भी नोटिस जारी कर सुनवाई का नियमानुसार एवं विधिसम्मत अवसर प्रदान किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.07.2017 को पेश हों।

12. निर्णय सुनाया गया।


(नत्थूराम)
सदस्य